

संपादकीय

मिलकर काम करें

केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पिछले कुछ समय से तीखा हो चला तानाव फिलहाल खत्म हुआ सा लग रहा है। दोनों पक्षों ने परिपक्षता का परिचय देते हुए विवादित मुद्दों के समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश की है। एक विशेषज्ञ समिति यह तय करेगी कि रिजर्व बैंक के पास पूँजी का कितना आरक्षित भंडार रहना चाहिए। इस समिति के सदस्यों के बारे में सरकार और रिजर्व बैंक दोनों मिलकर फैसला करेंगे।

रिजर्व बैंक का पूँजी आधार अभी 9.69 लाख करोड़ रुपये है। उसके स्वतंत्र निदेशक और आरएसएस के करीबी स्वदेशी विचारक एस. गुरुमूर्ति तथा वित्त मंत्रालय चाहते हैं कि इस कोष को वैश्विक मानकों के अनुरूप घटाया जाना चाहिए। विशेषज्ञ समिति इस कोष के उचित स्तर के बारे में अपनी सिफारिश देगी। सिस्टम में लिक्षिती यानी नकदी की कमी दूर करने के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी करने का फैसला लिया गया। आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद के जरिए इस रकम को सिस्टम में डालेगा। लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को कर्ज देने की नई नीति बनाने पर भी सहमति बनी। इसके तहत एमएसएमई के लिए 25 करोड़ रुपये तक का लोन स्वीकृत हो सकेगा। बैंकों की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के मामले में यह तय किया गया कि इस मुद्दे को रिजर्व बैंक का वित्तीय विरीक्षण बोर्ड देखेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 21 में से 11 बैंक पीसीए फेमवर्क के तहत लाए गए हैं। उमीद की जानी चाहिए कि रजामंदी के इन कदमों के बाद रिजर्व बैंक की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि सरकार उसके कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है और सरकार की यह धारणा भी धूमिल पड़ेगी कि रिजर्व बैंक उसके सुधार कार्य में बाधा बन रहा है। हालांकि, विशेषज्ञ समिति के गठन की बात कुछ अजीब लगती है क्योंकि रिजर्व बैंक खुद ही विशेषज्ञों की संस्था है।

बहरहाल, इस समिति के सदस्यों के चयन पर कोई बवेड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ अनुसुलझे मुद्दे अभी बचे हैं जैसे एनबीएफसी का मामला लेकिन सबसे बड़ा संकट आपसी विश्वास का है। आरबीआई के निदेशक मंडल में दो गुट बन गए हैं जिनमें एक सरकार को तात्कालिक लाभ पहुंचाना चाहता है तो दूसरा अर्थव्यवस्था को दूरगमी नजरिए से देखता है और उसे अर्थशास्त्र के स्थापित नियमों से चलाना चाहता है। इन दोनों समूहों में टकराव से स्थिति बेकाबू होती हुई लगने लगी थी। रिजर्व बैंक और सरकार में असहमति स्वाभाविक है पर किसी भी स्वायत्त संस्थान को ऐसा नहीं लगा चाहिए कि सरकार उसे अपनी कठपुतली की तरह चलाना चाह रही है। इससे उसका मनोबल कमजोर होता है और समाज में यह संदेश जाता है कि सरकार का जनतंत्र और पारदर्शिता में भरोसा कम है। सच्चाई यह है कि सरकार और रिजर्व बैंक का मकसद एक ही है—अर्थव्यवस्था को संभावित संकटों से बचाते हुए विकास की रपतार तेज रखना। इस काम को दोनों आपसी समझदारी से अंजाम दें, इसी में देश का फायदा है।

घर में बनाएं स्वादिष्ट- बैंगन भर्ता



बैंगन का भर्ता रेती और चावल दोनों के ही साथ बड़त अच्छा लगता है।

बच्चों को अगर

बैंगन की सब्जी

विधि— बैंगन को धोकर पोंछ लें। बैंगन के ढंगल को काटें नहीं क्योंकि इससे भूनते समय बैंगन को पकड़ना आसान रहता है। अब इसको पीड़ियम आंच पर अच्छे से भून लें। भूने के बाद पसंद नहीं आती तो उहें भर्ता बनाकर खिलाएं। जानेंगे इसकी ईजी

रेसिपी के बारे में।

सामग्री— बैंगन- 1 बड़ा, प्याज- 2 मीडियम, हरी मिर्च 3-4, अदरक- 1 डुंगे इंच का टुकड़ा, टमाटर- 2 मीडियम (कटे हुए), तेल 3-4 बड़ा चम्पच, जीरा डु छेटा चम्पच, हींग- 2 चुटकी, लाल मिर्च पाउडर- हुआ छेटा चम्पच, हल्दी पाउडर- 2 छेटा चम्पच, धनिया पाउडर- 2 छेटा चम्पच, मेथी पाउडर- 2 छेटा चम्पच, नमक- स्वादानुसार, गरम मसाला- हुआ छेटा चम्पच, कटी हरा धनिया- 2-3 बड़ा चम्पच

मालगाड़ियों के विशेष गलियारे से बदलेगा देश के लॉजिस्टिक्स का चेहरा: प्रभु

नई दिल्ली (आरएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने देश के भविष्य के लिए लॉजिस्टिक्स की सफलता को महत्वपूर्ण बताते हुये आज कहा कि माल ढुलाई के लिए बनाये जा रहे विशेष रेल गतियारों से देश के लॉजिस्टिक्स का चेहरा पूरी तरह बदल जायेगा।



मामले में किफायती थी, लेकिन मौजूदा सरकार के इनकारण से देश में माल परिवहन सस्ता होगा और इसमें समय की बचत होगी। विकास की अगली धारा का सुजन आपूर्ति श्रृंखला से होगा। हम एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना तैयार करेंगे। समय और लागत के

मालगाड़ी अपने गतव्य पर कब पहुँचेगी इसके बारे में सिर्फ भविष्य ही बता सकते थे क्योंकि मालगाड़ियों के लिए कोई समय-

सारणी नहीं होती भी ग्राहक योगी तो कोई भी ग्राहक योगी तो कोई भी समान भेजेगा।

2

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने बताया कि माल ढुलाई के लिए पूर्वी और पश्चिमी गलियारे मार्च 2020 तक बनकर तैयार हो जायेंगे तथा भविष्य में तीन और गतियारे तैयार करनी की योजना है। ये हैं— उत्तर-दक्षिण गलियारा, पूर्व-दक्षिण गलियारा और पूर्व-पश्चिम गलियारा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल मिश्रित यातायात के पुराने मॉडल से अब विशेष गलियारों के मॉडल की ओर बढ़ रहा है।

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80